मध्य प्रदेश और गुजरात में गरीबी उन्मूलन योजनाएं

863. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल** :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण, पिछड़े तथा जनजातीय लोगों के लिए पिछले तीन वर्षो के दौरान तैयार की गई गरीबी उन्मूलन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आंबटित की गई;

(ग) इस धनराशि के कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया है, तथा शेष धनराशि का उपयोग न किया जाने के क्या कारण है;

(घ) क्या राज्यों के नवगठित जिलों के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि का कोई विशेष प्रावधान किया गया है; और

(ड़) गुजरात, मध्य प्रदेश और उडीसा के नव गठित जिलों में ढ़ांचागत तथा बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने तथा निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटिल): (क) से (ख) जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम है जो केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों सहित देशभर में पिछड़े और जनजाति के लोगों पर विशेष बल देते हुए गरीबि रेखा से नीने जीवनयापन करने वाले ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए कार्यान्वित किए जा रहे है। तथापि, विगत तीन वर्षो के दौरान गरीबी उपशमन के लिए नयी योजना नहीं बनाई गई है । 1995-96, 1996-1997 और 1997-98 अर्थात् विगत तीन वर्षो के दौरान आबंटित की गई राशि तथा इस राशि के प्रतिशत उपयोग विवरण-। और ॥ में दिए गए है । (नीचे देखिए)

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजना आयोग द्वारा अनुमानित गरीबी अनुपात के आधार पर तथा जिलों को दिशा निर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निधियां आबंटित की जाती है । सुनिश्चित योजगार योजना एक मांग-आधारित योजना है और जिले उपलब्ध निधियों के 50% उपयोग के पश्चात् अगली किस्त ले सकते है ।

(ड़) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं और राज्य सरकारें ही गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उडीसा राज्यों के नए जिलों सहित देशभर के सभी जिलों के गावं, विकास खण्ड तथा निला स्तरों पर कार्यक्रमों की पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए तथा प्रभावी कार्यान्वियन की आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों, केन्द्र/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जा कर जांच करके निगरानी करती है ।

विवरण –।

मध्य प्रदेश को विगत तीन वर्षो अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आबंटित की गई राशि तथा प्रतिशत उपयोग

कार्यक्रम	1995-1996		1996-1997		1997-98	
	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	उपयोग
जे.आर.वाई.	51119.46	82.90	22014.51	89.59	24597.23	78.30
ई.ए.एस.*	22940.00	100.05	22670.17	106.88	21507.85	111.40
आई.आर.डी.पी.	10565.39	107.01	10565.39	127.49	10914.93	109.90

* सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है, आंकड़े आबंटन की बजाए केन्द्रीय रिलीज को दर्शाते है ।

विवरण-II

गुजरात को विगत तीन वर्षो अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आबंटित की गई राशि तथा प्रतिशत उपयोग

कार्यक्रम	1995-1996		1996-1997		1997-98	
	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग	आबंटित की गई राशि (रु. लाख में)	% उपयोग
जे.आर.वाई.	14754.11	86.92	6376.25	98.50	7124.30	98.25
ई.ए.एस.*	6970.00	85.52	5850.00	129.42	4320.00	152.97
आई.आर.डी.पी.	3059.22	100.60	3059.22	98.93	3160.43	107.48

* सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है, आंकड़े आबंटन की बजाए केन्द्रीय रिलीज को दर्शाते है ।

Funds for rural employment in West Bengal

864. SHRI .S.RAMACHANDRAN PILLAI: SHRI E. BALANANDAN:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of targets and achievements set out by Government for rural and tribal people of West bengal in Eighth Plan period and for the Ninth Plan period; and

(b) the year-wise allocation of funds by Government for rural employment schemes projects initiated in States during Eighth Plan period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND-• EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) Jawahar Rozgar Yojana (JRY), Employment Assurance Scheme (EAS), Million Wells Scheme (MWS) and Integrated Rural Development Programme (IRDP) are the major employment schemes being implemented by the Government throughout the country including in the State of West Bengal. No targets are fixed for employment generation for SCs and STs under JRY and EAS as the schemes are self-targetted. However, the mandays generation are monitored separately for SCs and STs. Under MWS, not less than 2/3rd of the funds are to be spent on SCs &STs. Similarly, under IRDP 50% of the beneficiaries are to be selected from SCs and STs. Details of targets and achievements of JRY, EAS, MWS and IRDP programmes during the Eighth Five Year Plan and for the Annual Plan 1997-98 in respect of West Bengal are given in Annexure *[See Appendix 184, Annexure No. 25]*

(b) The year-wise allocation of funds for the major employment schemes such as JRY, MWS and IRDP during 8th plan period is given at Annexure [See Appendix 184, Annexure No. 25(A)] No allocation are made under EAS. However the releases made under EAS are given at Annexure [See Appendix 184, Annexure No. 25(A)]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को हुआ घाटा

865. **श्री ईश दत्त यादव** :
श्री राम गोपाल यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को कुल कितना घाटा हुआ है और ऐसी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के लगातार बढ़ते हुए घाटे को कम करने के लिए कोई ठोस और कारगर कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) एन.टी.सी. के अपने नियंत्रणाधीन 119 मिलें है । वर्ष 1997-98 के लिए एन.टी.सी. का अनतिम कुल निबल घाटा 685.56 करोड़ रुपए है ।

(ख) और (ग) सरकार एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधर पर एन.टी.सी. की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वागीण सुधार नीति पर विचार कर रही है जिसके लिए वी.आई.